(1200/MM/RU)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में घोषणा

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तदापि इनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसर पर उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमें भी तो कोई मामला उठाने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : क्या है?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आप जानते हैं कि यह सरकार फौजों का नाम लेकर सत्ता में आयी है और सत्ता में आने के बाद ये फौजों के ऊपर अन्याय कर रही है। नि:शक्त फौजियों को जो पेंशन मिलती है, उसके ऊपर इन्होंने कर लगाना शुरू किया है। उनसे कर वसूला जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे हमारी फौजों का अपमान हो रहा है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 3, श्री रत्न लाल कटारिया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री रतन लाल कटारिया।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वैपकोस लिमिटेड तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

MOTION RE: FIRST REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri Pralhad Joshi, I beg to move:

> "That this House do agree with the First Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 26th June, 2019."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 26 जून, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN TEACHERS' CADRE) BILL

1203 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY DHOTRE): On behalf of Shri Ramesh Pokriyal 'Nishank', I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the reservation of posts in appointments by direct recruitment of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the socially and educationally backward classes and the economically weaker sections, to teachers' cadre in certain Central Educational Institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और सहायता प्राप्त कतिपय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI SANJAY DHOTRE: I introduce the Bill.

STATEMENT RE: CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN TEACHERS' CADRE) ORDINANCE - LAID

1204 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY DHOTRE): I beg to lay on the Table an explanatory Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediately legislation by promulgation of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (No. 13 of 2019).

(1205/SJN/NKL)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक

1205 hours

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 5) के बारे में विवरण – सभा पटल पर रखा गया

1206 hours

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 5) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक

1207 hours

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विशेष उल्लेख

1208 बजे

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मोहम्मद जावेद।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लिस्ट पूरी होने के बाद बोलिएगा।

…(व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : महोदय, मैं किशनगंज से चुनकर आया हूं और मेरे क्षेत्र में कई नदियां हैं, जैसे महानंदा डोक, कनकई कोल, रेतुआ, मेंची, रमजान। इनकी वजह से पानी तो मिलता है, लेकिन तबाही भी बहुत होती है। यूपीए सरकार के वक्त महानंदा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट चलाने की बात हुई थी। लेकिन पिछले पांच सालों में इस पर कोई नतीजा नहीं निकला है। आपको बताते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि हर मानसून में फ्लड्स की वजह से हमारी हजारों एकड़ भूमि का नुकसान हो जाता है। कई स्कूल, मदरसे, ग्रेवयार्ड, मंदिर और मस्जिद भी ढह गए हैं।

मेरी आपके माध्यम से यह गुजारिश है कि इस महानंदा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट को फिर से चालू किया जाए, ताकि जो तबाही हुई है और हो रही है, उसको रोका जा सके।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभागृह का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र से रिलेटेड लोकल रेलवे सेवा पर आकर्षित कराना चाहता हूं। लोकल रेलवे सेवा मेरे संसदीय क्षेत्र की लाइफ लाइन है, परंतु पिछले कुछ दिनों से इस सेवा में किसी न किसी तरह का व्यवधान प्रतिदिन देखने को मिलता है। कभी रेलवे ट्रैक फ्रैक्चर हो जाता है, कभी पैन्टोग्राफ फेल्योर हो जाता है, तो कभी सिग्नल यंत्रणा में तांत्रिकी खराबी हो जाती है। खासकर ठंड और बारिश में रेलवे ट्रैक का बिगड़ना मानो एक आम बात हो चुकी है। बारिश में ट्रेनें रोज 10 से 15 मिनट लेट ही चलती हैं। सतत् रूप से लेट चलने वाली ट्रेनों के कारण लाखों लोगों का लेटमार्क लगता है। प्रतिदिन 42,50,000 यात्री मध्य रेलवे के सेन्ट्रल हार्बर और ट्रांस-हार्बर मार्ग पर यात्रा करते हैं। रोजाना 1,772 लोकल सेवाएं इस उपनगरीय रेल लाइन पर चलती हैं। पिछले एक महीने से ट्रेनें लगभग रोज लेट हो रही हैं।

महोदय, हर रविवार को साल के 52 दिनों में मेगाब्लाक होता है। इसके बावजूद सब अर्बन रेलवे अपने नियमित समय पर नहीं चलती है।

मैं आपके द्वारा रेल मंत्री जी के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि सब अर्बन रेलवे से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है और सबसे ज्यादा जो समस्या है, वह इस सब अर्बन रेलवे की ही है। सप्ताह में पांच दिन इसका टाइम टेबल बिगड़ा रहता है।

अतः मेरे कुछ सुझाव हैं कि जो पानी की समस्या है और बारिश में जो ट्रेनें लेट होती हैं, तो जिन नालों की सफाई नहीं होती है, उनकी सफाई बारिश से पहले जल्द से जल्द की जानी चाहिए।

(1210/GG/KSP)

बड़े हॉर्स पॉवर के पंप्स लगाने चाहिए। उसी के साथ मेरे संसदीय क्षेत्र में मुंबई-कल्याण रेलवे मार्ग पर यातायात जब भी बाधित हो, तभी कल्याण से कसारा और कल्याण से कर्ज़ट जाने वाले मार्ग के यातायात को निरंतर जारी रखने के लिए कर्ज़ट-कसारा मार्ग पर ज्यादा लोकल ट्रेन्स उपलब्ध रखें।

…(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। महोदय, मैं बिहार के पूर्णिया जिले से आता हूँ, जो पटना से साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर है। वहां पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापित करने की मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ, ताकि हमारे इलाके के गरीब लोगों को केस लड़ने के लिए साढ़े तीन सौ किलोमीटर की दूरी न तय करनी पड़े। पूर्णिया में हाई कोर्ट की बेंच खुल जाने से वहां पर मुकदमा लड़ने वाले लोगों एवं अधिवक्ताओं को आसानी होगी। वहां पर आस-पास के जो परिमण्डल्स हैं, पूर्णिया के साथ-साथ कोसी परिमण्डल और भागलपुर परिमण्डल के लोगों के लिए भी यह लाभदायक होगा। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार को निर्देश दें कि पूर्णिया में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना हो। हम आपके माध्यम से इस बारे में कानून मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव प्रताप रूडी एवं श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को श्री संतोष कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Hon. Speaker, Sir, I request the Government, through this august House, to kindly take urgent steps to stop the unethical practice of withholding the certificates of students by educational institutions. Most students avail the facility of educational loans for paying their fees. Due to various bank formalities, the promised loan amount is not sanctioned in time of their admission by which time the students will have to join the course. Unable to pay the fees, the students who might want to discontinue the course are put through more trials owing to the fact that the educational institutions refuse to return their certificates and they are not able to join another institution. It should be noted that there is an existing Delhi High Court order dated July 20, 2011 which states that educational institutions should not withhold the certificates of students, but only verify it at the time of admission for its credibility. Lakhs of students in the country are now trapped in this malpractice of educational institutions thus preventing them from pursuing a future of their choice. If the banks sanction educational loans in a time-bound manner, exploitation of the students by educational institutions can be stopped.

Therefore, I request the Government to kindly take urgent steps to stop the unethical practice of the banks and educational institutions in exploiting the students in this manner.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, डॉ. संजय जायसवाल एवं एडवोकेट ए.एम. आरिफ को श्री एंटो एन्टोनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Speaker, Sir, this House has already been exercised over the death of children in the S.K. Medical College and Hospital, Muzaffarpur. The death toll has touched 150. Though the Health Minister went there, so far, he has not made any statement in this House on the reason of death of many children.

Now, new facts have come to light about the Central Government-run Kalawati Saran Children's Hospital, which is a super-speciality hospital in Delhi. It is reported that in six years over 6,000 child deaths were reported at Kalawati Hospital which is a referral hospital for children from all over India. The most common cause of death at the hospital include premature births, respiratory infections, septicaemia and other infections and 50 per cent of the deaths are reported in the first 48 hours of admission, which indicates a serious condition of the people. The infrastructure in the Kalawati Saran Hospital are inadequate to meet the demands of the patients. In this case, I think the Government of India can take a lesson from West Bengal, where the Government under Mamata Banerjee have set up a large number of SNCUs and have brought down the number of child deaths drastically and have also brought down MMR drastically.

The Government should make efforts to improve the facilities in the Central Government-run Hospital in Delhi and take steps throughout the country to reduce child deaths due to inadequate facilities.

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब एवं श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1215/SRG/KN)

श्री दुर्गा दास (डी.डी) उईके (बैतूल): परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, सादर अभिवादन। मैं आपके माध्यम से लोक सभा में प्रथम बार भावाभिव्यक्ति का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के भाइयों और बहनों व युवा साथियों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनकी कृपा से यह पावन अवसर उपलब्ध हुआ है। मैं माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय श्री अमित शाह जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी कृपा से यह मार्ग प्रशस्त हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लोक हित के मुद्दे को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। बैतूल हरदा हरसूद लोक सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश का जनजाति बहुल जिला है। बैतूल जिले को भारत माता की हृदय स्थली भी कहा जाता है। यह जिला कभी सघन वनों से आच्छादित था। इमारती लकड़ियों, वन औषधियों एवं वन उपजों के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासी भाइयों और बहनों का आर्थिक जीवन इन्हीं पर आश्रित रहा है। किन्तु जिस निर्ममता और बर्बरतापूर्वक वनों की कटाई हुई है, वन सम्पदा को भारी क्षति पहुंचाई गई है, उसके कारण क्षेत्र में प्राकृतिक असंतुलन की स्थितियाँ निर्मित हुई हैं। आदिवासी समाज पलायन के लिए मजबूर हुआ है। मैं 10 वर्षों तक मेरे लोक सभा क्षेत्र में शासकीय, अशासकीय स्तर पर वनों की कटाई पर रोक लगाने हेतु विनम्र अनुरोध करता हूँ, ताकि प्राकृतिक रूप से वनों का संरक्षण अभिवर्धन हो सके।

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत बधाई। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, साथ ही साथ इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी व भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ।

मान्यवर, मैं इस प्रश्न के माध्यम से मेरे लोक सभा क्षेत्र बदायूं का दु:ख व्यक्त कर रही हूँ। आज़ादी के 72 वर्षों बाद भी बदायूं के लोगों को सीधे-सीधे लखनऊ व दिल्ली रेल मार्ग की सुविधा नहीं मिल पाई है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या बदायूं को लखनऊ व दिल्ली रेल मार्ग से जोड़ने की कोई योजना है अथवा नहीं? यदि है, तो उसके बारे में कृपा अवगत कराएं। यदि नहीं है, तो उस पर विचार करने की कृपा करें। साथ ही साथ मैं बदायूं लोक सभा क्षेत्र के गुन्नौर विधान सभा के अंतर्गत बबराला स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ी संख्या 14320 व 14321 महाकाल एक्सप्रेस का ठहराव चाहती हूँ, जिससे वहाँ की जनता लाभान्वित हो सके।

अंत में, मैं लोक सभा बदायूं की समस्त सम्मानित जनता का व अपने शुभचिंतकों का इस संसद भवन से बहुत-बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती अपरूपा पोद्दार। अनुपस्थित।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और एल एंड डीओ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में सीलिंग की जो समस्या चल रही थी, उसका एक हिस्सा ठीक हुआ है। लाजपत नगर के क्षेत्र में जहाँ पर लीज डीड एग्जिक्यूट की है, 40-50 साल पुरानी प्रॉब्लम है, आज़ादी के बाद जो रिफ्यूजीज आए थे, उनके क्षेत्रों की प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके अलावा अन्य प्रॉब्लम्स बहुत अधिक हैं, खास तौर पर लोकल शॉपिंग सेंटर्स को लेकर। मेरे यहाँ पर 20 से ऊपर लोकल शॉपिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पर जमीन कमर्शियल है, दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर एक जमाने में शॉप-कम-रेजिडेंशियल एरिया होता था। अब सब ने थोड़ा पैसा कमा लिया तो ऊपर रहना बंद कर दिया और मकान अलग बना लिए। उस क्षेत्र को रेजिडेंशियल ट्रीट करके सीलिंग की व्यवस्था, जब एफ.ए.आर. जो बाकी इलाके रेजिडेंशियल हैं, वहाँ पर बढ़ा दिया गया, लेकिन लोकल शॉपिंग सेंटर्स के अंदर एफ.ए.आर. को नहीं बढ़ाया गया। ऐसा

प्रतीत होता है कि जैसे एनकरेज किया जा रहा है कि रेजिडेंशियल इलाकों में आप कमर्शियल एक्टिविटी करें और कमर्शियल इलाकों को इतना महँगा कर दें कि वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी न हो पाए।

(1220/CS/RP)

इसी के रहते एमपीडी को जब ठीक किया जा रहा है, जब उसमें अमेंडमेंट लाए ला रहे हैं तो मेरा आग्रह है कि इन सबकी चिंता करते हुए एफएआर को लोकल शॉपिंग सेन्टर्स के लिए बढ़ाया जाए। बेसमेंट्स अलाऊ करके व्यक्तियों को न बैठने दिया जाए, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था में लॉकर आदि को जो रखने की जो व्यवस्था है, वह अलाऊ की जाए, जो बाकी जगहों पर अलाउड है। कमर्शियल, रेजिडेंशियल के जो कन्वर्जन चार्जेज हैं, उन्हें पैरलल किया जाए और उसी के रहते जो ए,बी,सी कैटेगरी की कॉलोनीज हैं, उनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी किसी भी तरीके से न हो, उसके लिए वहाँ पर रेट्स बढ़ाए जाएं, न कि बराबर किए जाएं। बाकी सब जगह पर कन्वर्जन चार्ज को बराबर किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सी.पी. जोशी को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय कुमार (खीरी): महोदय, 100 से अधिक ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन वन विभाग की एनओसी न मिल पाने के कारण वे प्रारम्भ नहीं हो पा रहे हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730, जो खुटार-सिसिया120 किलोमीटर चौड़ीकरण होना है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731, जो पलिया से शाहजहांपुर के बीच बन रहा है, एक वर्ष पूर्व इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, लेकिन वन विभाग की एनओसी न मिल पाने के कारण इसका काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। उसका दुखद पहलू यह है, चूँकि प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है, इसलिए सड़क की मरम्मत का काम भी रोक दिया गया है। मरम्मत का काम न होने के कारण वहाँ बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और सड़कें टूटी हुई हैं। इसके कारण दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ी हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक नई कार्य-विधि विकसित करें, जिसमें टेंडर आदि प्रक्रिया भले ही पूरी हो जाए, लेकिन जब तक सड़क का काम पूरी तरह से शुरू न हो जाए तब तक मरम्मत के कामों को न रोका जाए। सड़कों, खासकर राष्ट्रीय राजमार्गों की नियमित मरम्मत की व्यवस्था की जाए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Speaker, Sir, I wish to draw the attention of this House to a very important topic. In December, 2018, the then Minister for Information and Broadcasting, Mr. Rathore said on the Floor of the House that the Government, from the years 2014 till December, 2018, had spent approximately Rs. 5,246 crores on advertising. This was only the Central Government's expenditure. It does not include public sector undertaking expenditure, which, I believe, forms the bulk of it. Given that this is the tax payers' money and what the PSUs are spending is also the tax payers' money, we need to have a better idea what the total advertising spending is. You can see, in 2014-15, it was Rs. 979 crores, which went up to about Rs. 1,300 crores in 2017-18. Five of the largest news media organisations in this country are either owned or indirectly debted to one person. He is the richest Indian. He is an associate who is on the Board of the largest telecom venture. News Nation, India TV, News 24, Network 18, NDTV are all owned….(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri B. Manickam Tagore.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Let me finish, Sir. We want to know as to what is the breakup of the adspend via media houses and if certain print media are being excluded. This is very important.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Respected, Speaker, Sir, I would like to draw your attention to water crisis in Tamil Nadu, particularly, in the Southern Part of Tamil Nadu. The Districts of Madurai and Virudhunagar are mostly affected. The major lapse of the State Government is that for the last eight years they are only encouraging the sand mafias to dig the rivers and ponds. The State Government has completely failed in water management.

Therefore, I request the Central Government to intervene and send a Central team to Tamil Nadu and help them in solving the water problem. Each village is without water. The water problem is a big problem in Tamil Nadu. Even the New York Times wrote a story on this problem. The Tamil Nadu State Government is just blind not to see what is happening there. I request the Central Government to send a team to solve this problem.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, धन्यवाद। एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम या इंसेफलाइटिस सिंड्रोम हम आज भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमें यू.के. इंग्लिश बोलनी है या यू.एस. इंग्लिश बोलनी है। चमकी बुखार का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। कल राज्य सभा में माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था कि बच्चों का बुखार से मरना देश की 70 सालों में विफलताओं की एक बहुत बड़ी पहचान है।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि जो पाँच वाइरोलॉजी सेन्टर्स बिहार में खुल रहे हैं और पटना में दो सेन्टर्स खुल रहे हैं। पटना में चमकी बुखार का प्रकोप नहीं होता है। बेतिया गोरखपुर और मुजफ्फरपुर के बीच में है।

(1225/RV/RCP)

गोरखपुर में भी चमकी बुखार से बच्चे मरते हैं और मुज़फ्फरपुर में भी मरते हैं, पर इन दोनों के बीच जो पश्चिम चम्पारण जिला है, वहां ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। वहां वाइरोलॉजी सेन्टर खोला जाए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कृपा करके यह सुनिश्चित करें कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक ब्लड ग्लूकोमीटर हो और यह बता दिया जाए कि 10 पर्सेंट डेक्स्ट्रोस दवा चढ़ा देने से बच्चे मरने से बच सकते हैं क्योंकि बीमारी के बारे में तो हमें पता नहीं है।

दूसरा, इसका प्रचार कम से कम मार्च से गोरखपुर, चम्पारण और मुज़फ्फरपुर के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चारों तरफ हो ताकि जिसके बच्चे को यह बुखार हो, वह डॉक्टर से मिले। अगर आप इतना करवा देंगे तो इससे देश को बहुत बड़ी मदद होगी।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता और श्री सी. पी. जोशी को डॉ. संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): ऑनरेबल स्पीकर सर, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए और महान भारत के इस पार्लियामेंट से भी मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। चाइनीज़ ऑब्जेक्शंस के कारण वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जाइका और किसी की भी फंडिंग अरुणाचल प्रदेश में दस-पन्द्रह सालों से नहीं हो रही है। यू.पी.ए. वन में मनमोहन सिंह साहब ने अरुणाचल प्रदेश को यह वादा किया था कि चाइनीज़ ऑब्जेक्शंस के कारण वर्ल्ड बैंक से हम फण्ड्स नहीं दे पा रहे हैं, पर in lieu of this, एक अल्टरनेट फंडिंग हम अरुणाचल प्रदेश को देंगे।

स्पीकर साहब, इसमें आपका इसलिए प्रोटेक्शन चाहिए कि आज अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हजारों स्कीम्स में वर्ल्ड बैंक से जो फंडिंग होनी है, वह चाइनीज़ ऑब्जेक्शंस की वज़ह से हो नहीं पा रही है। मैं गवर्नमेंट-ऑफ-इंडिया से माँग करता हूं कि अगर वर्ल्ड बैंक से फंडिंग नहीं हो पा रही है तो इसके अल्टरनेट के रूप में, in lieu of that, अरुणाचल प्रदेश को अलग स्कीम्स सैंक्शन की जाए, ताकि अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। मैं यही माँग करता हूं।

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram is one of the premier institutions for providing cardiology, neurology, and neurosurgery services. A lot of patients from every part of Kerala are going there for treatment. But, unfortunately, Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is not implemented in that institution. This is a public institution. The Kerala Government has also complained about this.

So, I urge upon the Health Ministry to implement this Scheme in Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, एडवोकेट अदूर प्रकाश और एडवोकेट ए.एम. आरिफ को श्री के. मुरलीधरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर बात मेरी कंस्टीट्युन्सी दादरा और नागर हवेली के बारे में उठाना चाहता हूं।

सर, यह एक केन्द्रशासित प्रदेश है, जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है। वहां सारे के सारे अधिकार प्रशासन के पास और प्रशासन के अधिकारियों के पास हैं। वहां के लोगों की काफी पुरानी और स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि वहां पर लेजिस्लेचर बनाया जाए, वहां पर विधान सभा गठित की जाए। यह बहुत पुरानी माँग है।

सर, वर्ष 2014 में महामहिम उप राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में होम मिनिस्ट्री की स्टैन्डिंग कमेटी ने वहां की विजिट की थी और उन्होंने पूरी जाँच की। जाँच के बाद उन्होंने यह पाया कि यहां पर लेजिस्लेचर दिया जा सकता है, विधान सभा दी जा सकती है। अभी भी वह प्रपोजल पेन्डिंग है। वह सारी रिपोर्ट राज्य सभा में टेबल हुई है। इसके लिए हम वहां पर पॉपुलेशन वाइज, रेवेन्यू वाइज वाएबल हैं। पूरे विश्व में भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, फिर हम क्यों वंचित हैं? हमारे यहां क्यों नहीं

है? मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस रिपोर्ट पर तुरन्त कार्रवाई करे और विधान सभा के गठन के लिए काम शुरू करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मानव जीवन में भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा का विशेष महत्व है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र अकबरपुर, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, जो कानपुर मंडल के अन्तर्गत आता है, जिसके अन्तर्गत छ: जनपद आते हैं, उसके सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ दस जनपद, जो बुन्देलखण्ड और उसके आस-पास के हैं, वहां के लोग उस अस्पताल में आते हैं।

(1230/MY/SMN)

महोदय, उत्तर प्रदेश में तीन एम्स (गोरखपुर, रायबरेली और बीएचयू-वाराणसी) की स्थापना की गई है। उक्त स्थापित एम्स से उत्तर प्रदेश के मात्र पूर्वी क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी, जबकि यदि कानपुर मेडिकल कॉलेज को एम्स बनाया जाए तो लगभग 15 से अधिक जनपदों की जनता को उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में अभी तक कोई एम्स स्थापित नहीं हुआ और न ही स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा व पुराना मेडिकल कॉलेज है। यह कानपुर नगर एवं आस-पास के लगभग 15 से अधिक जनपदों को उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इस महाविद्यालय में प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण भी किया जा रहा है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, Chengannur and Kuttanad regions are in my Parliamentary Constituency and had suffered the worst in the aftermath of 2018 floods. Despite assurances from the Governments, the

rebuilding initiatives are incomplete and Chengannur-Kuttanad region needs a special package and master plan. The strengthening of river banks, support to agriculture, dairy sector, support to tourism sector, revamping of irrigation systems including construction and strengthening of padasekharam bunds, and potable water supply must assume priority.

I would urge the Government to establish a special central Government package with budgetary allocations made and institute a dedicated expert committee to monitor the progress and ensure completion of works in a time bound manner.

I would also like to request the Government of India to set up Kuttanad Development Authority to look after the development of Kuttanad and sort out the problems of people of Kuttanad from time to time.

Holy Pampa river also is in worst condition. I urge upon the Government to implement Pampa Action Plan immediately.

*SHRI Y. DEVENDRAPPA (BELLARY): Hon.Speaker, Sir, at the outset I congratulate you for giving me the opportunity to speak during zero hour.

I would like to draw the attention of the union government that farmers in Bellary district grow Onion, Chilly, and other crops. I would like to request the Union government should take immediate steps to set up of cold storage units to encourage our farmers.

Another point I would like to mention that the river Tungabhadra has the capacity of 32.471 TMC of water storage. However due to siltation in the water storage capacity of the river has come down. About 48.88 TMC of water is of no use due to siltation. De-siltation work should be taken up without any delay. So it would be beneficial to the farmers.

Therefore, I urge upon the union government through you to take measures to de-silt the river Tungabhadra to increase the water storage and enable farmers to make utilize it. Thank you.

Jai Jawan, Jai Vigyan, Jai Kisan.

---

* Original in Kannada.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): Sir, on 9th June, 2019, one elderly patient was brought to NRS hospital, Kolkata in critical condition. In spite of all the efforts, the patient could not be saved. The relatives of the patient attacked the junior doctor and two doctors are seriously injured. This incident has brought the issue of increasing violence against doctors and this kind of incidents are increasing all over the country. We must understand that, in spite of all the advances in the medical field, there are limitations to medical treatment. In spite of all efforts, it is not always possible to save the patient and probably, this was misinterpreted by the patient's relatives as negligence. In treating critical patients and operating the major and *supra*-major surgery, it carries the risk of complication, morbidity and mortality. Hence, there is a very thin line between inevitable complication and negligence.

It is also important to understand that doctors are also human beings and not healing angels. It is unacceptable and absurd to victimise a medical practitioner if a patient does not respond to the treatment. Violence against doctors is unacceptable and any such act should be made a punishable, non-bailable offence with imprisonment.

(1235/MMN/CP)

I congratulate the Health Minister, Dr. Harsh Vardhan Ji who has written letter to the Chief Ministers of all the States, asking them to bring legislation to protect the doctors and also to ensure that the law is implemented in States where such laws are already in place. He also circulated the copies of the draft

Protection of Medical Service Persons and Medical Service Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss of Property) Act, 2017 to the States. Today, 19 States have some legislation, legal provision, and many have promulgated the Ordinance. Since health is a State subject, I urge all the State Governments to strictly enforce the provision of special legislation to protect the medical community and to provide security to the hospitals. There should also be a Central Act to this effect.

Speaker, Sir, I appeal to you, let us have a detailed deliberation on this issue because the relation between doctor and patient is very crucial for the public health system. So, we must have deliberation on this in the form of a Short Duration Discussion.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायसवाल, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री सुधीर गुप्ता और श्री सी.पी. जोशी को डॉ. सुभाष रामराव भामरे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय नए सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे शून्य काल में अपना जो विषय उठाना चाहते हैं, उसको संक्षिप्त में टेबल आफिस में दें और उसमें हल्की सी विषय वस्तु लिखें कि किस विषय पर आप शून्य काल उठाने जा रहे हैं। मैंने कल भी सभी माननीय नए सदस्यों को इजाजत दी थी। मैं आज भी माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करूंगा कि वे संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड बन गया है। इतने ज्यादा सदस्यों को पहली बार मौका मिल रहा है। आपको बधाई हो।...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : बधाई हो।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय नए सदस्य।

...(व्यवधान)

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): देश में लगभग सभी एमपी पर यह बात लागू होती होगी कि जो बैंकिंग में ऋण लेने की प्रथा है, जो बैंकिंग में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के मार्फत जो बैंकेबल योजनाएं की एप्लीकेशंस होती हैं, वे एप्लीकेशंस इतनी बड़ी होती हैं कि कागजात तैयार करने में भी बेनेफिशियरी को बहुत टाइम लगता है।...(व्यवधान) उसके बाद जब वे बैंक में जाते हैं, तब बैंक बहुत समय के बाद न बोलते हुए कहती हैं कि आपको यह कर्ज नहीं दिया जाएगा। ...(व्यवधान)

मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि हर लोग, जो डीआईजी है, डीआईसी के माध्यम से इतनी एप्लीकेशंस बैंक के कंसर्न में रहकर इतनी होनी चाहिए, जितने को बैंक लोन दे। इसमें बेनेफिशियरीज का भी कोई खर्च न हो। इसी वजह से ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले नए माननीय सदस्य बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): मैं इसलिए बोलता हूं कि हर जगह बैंकेबल योजनाएं होती हैं। बैंकेबल स्कीम के मुताबिक बैंक में ऋण लेने की प्रथा है। वैसे तो मैं धन्यवाद देश के लोक लाड़ले प्रधान मंत्री को देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नए माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इसके बाद आपको मौका देंगे।

...(व्यवधान)

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): जिन्होंने हर एक को बैंक में जाने का मौका दिया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री श्याम सिंह यादव।

…(व्यवधान)

…(*Interruptions*)

1238 hours

(*At this stage, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood near the Table.*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हम लोगों को निकाल दीजिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री श्याम सिंह यादव।

…(व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस समय कैसे बोलूं? कुछ सुनाई तो दे। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस सदन में मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज अपनी-अपनी सीट पर जाइए।

…(व्यवधान)

(1240/NK/VR)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. आर.के. रंजन- उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN): Thank you, Speaker, Sir, for giving me this opportunity. …(*Interruptions*)

India's rate of unemployment doubled in the past two years, according to the *State of India's Environment (SoE) In Figures, 2019*. …(*Interruptions*) This has particularly affected the young graduates. …(*Interruptions*)

While unemployment remains high in both urban and rural India, job hunting is a bigger challenge for the young and educated youth. According to the report, the unemployment rate has gone up from 4 per cent to 7.6 per cent in the last two years. …(*Interruptions*) The World Bank says that India needs to create around 81,00,000 jobs per year to solve the problem of unemployment. …(*Interruptions*)

However, standing in 2019, India could definitely achieve the honour of 'unemployment capital' of the world. …(*Interruptions*) The common people of the country wants an account of Rs.3400 crore budget allocated to the Skill India Mission in the Union Budget 2018-2019.....(*Interruptions*)

Through you, Sir, I request the Government of India to solve the issue of unemployment in India. …(*Interruptions*)

Thank you, Sir.

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं त्रिपुरा से आती हूं, यह नार्थ ईस्ट का छोटा सा स्टेट है। यह हमारे स्टेट का विषय है। हमारे स्टेट में

एयर कनेक्टिविटी बहुत कम है। ...(व्यवधान) दिल्ली से सिर्फ एक ही फ्लाइट है, जो सुबह पांच बजकर पैंतालीस मिनट पर जाती है। हमको दिल्ली से डॉयरेक्ट फ्लाइट चाहिए। कोलकाता से त्रिपुरा के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैं आपके माध्यम से नागर उड्डयन मंत्री से रिक्वेस्ट करती हूं। ...(व्यवधान) जल्द से जल्द दिल्ली से हमारे स्टेट के लिए एयर कनेक्टिविटी हो, कोलकाता से भी एयर कनेक्टिविटी जोड़ा जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को सुश्री प्रतिमा भौमिक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, इसके साथ-साथ मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय नीतीश जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मुखिया से लोक सभा पहुंचाने का काम किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया है। मैं बिहार के झंझारपुर से आता हूं। हमारे बिहार में पानी का बहुत संकट है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में जलसंकट दूर करने की कोशिश करें। कोशी, कमला, बलान नदियां नेपाल से आती हैं। वहां जल स्तर की बहुत कमी है। बच्चों को नहलाने और पानी पिलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यह बहुत सारी बीमारियों की जड़ है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस ध्यान देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री रेबती त्रीपुरा (त्रिपुरा पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं ट्राइब्ल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट में 10 ऐसे एडीसी हैं। इस साल 23 जनवरी को एडीसी को और पावर और फण्ड देने के लिए कैबिनेट में डिसीजन हुआ।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह कब होगा और यह अभी कौन-सी स्थिति में है। दूसरी बात यह है कि पीपरा में जो एडीसीज हैं, उनमें सिर्फ 28 सीट्स हैं। मैं उन सीट्स को 50 करने के लिए डिमांड करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रेबती त्रीपुरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1245/SAN/SK)

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity. …(*Interruptions*)

I am a first-time Member of this House. I have to mention that in the past few days, in this House, every Member has been very supportive and encouraging, irrespective of his age, party and region. I feel very confident of the future of our country. …(*Interruptions*)

I am now raising an issue which matters to our national security. I am concerned about the changing political scenarios around the world. I understand that India started out as a non-aligned member, managing to stay consistent, moving either closer to the left at times or closer to the right at other times. Our hon. Prime Minister's efforts too are commendable. …(*Interruptions*)

There seems to be a dramatic shift in the West from where one would expect the least. The United Kingdom surprised us with Brexit and the United States continues to surprise us each and every day. Self-protectionism seems to be taking precedence over world leadership. It might be a blunder not to expect more of these changes in the near future which might be more dramatic in nature. I hope, we are prepared for all eventualities either in trade or on security. When I say security, I also mean the millions of India living abroad. …(*Interruptions*)

I understand that the Government cannot reveal the roadmap for each likely scenario, but I would request the Government to put in place a mechanism to predict them and be prepared. I hope, we will not be caught off guard, like when America decided to withdraw our trade benefits or like when our immediate neighbours decided in the recent past to give priority to someone else over us. …(*Interruptions*)

Thank you.

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री श्रीधर कोटागिरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से अधीर रंजन चौधरी जी से कहना चाहता हूं। …(व्यवधान) अधीर रंजन जी, मैं आपकी बात ही कह रहा हूं, आपने एजर्नमेंट मोशन दिया और आप इस पर बोल भी चुके हैं। रक्षा मंत्री जी आए हैं, अगर अध्यक्ष जी अलाऊ करते हैं तो रक्षा मंत्री जी जवाब देने के लिए भी तैयार हैं।…(व्यवधान) हम सेना का सम्मान करने वाले लोग हैं। …(व्यवधान) वन रैंक वन पेंशन भी मोदी सरकार ने दी है। आपने खाली टोकन एमाउंट रखा था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सब सीट पर बैठिए।

…(व्यवधान)

1210 बजे (इस समय श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आपसे आग्रह करता हूं कि मैंने एक बार आपको व्यवस्था दी थी कि नए माननीय सदस्यों के बोलने के बाद आपको मौका दिया जाएगा और आप वैल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह उचित नहीं है। यह अंतिम मौका होगा। मैंने जब आपको व्यवस्था दी थी कि मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा। आप पहली बार आने वाले माननीय सदस्यों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं नया मैम्बर नहीं हूं, मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। आप नए मैम्बर्स को एक बार नहीं सौ बार चांस दीजिए। हमने सारे मैम्बर्स, जिनका नाम बैलेट में है, की बात करने की मांग की है, वह भी आप नहीं दे रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात कहें।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हमारे ऊपर इल्ज़ाम न लगाना अच्छा होगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, बात यह है कि अभी एक सीबीडीटी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। 24 जून, 2019 में एक सर्कुलर जारी किया गया है, नि:शक्त फौजियों को जो पेंशन मिलने वाली थी, उनके ऊपर कर लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है। नि:शक्त फौजी, जो जोखिम उठाते हुए खुद जख्मी हो जाते हैं तो वे नौकरी छोड़कर सुपरएनुएशन के जरिए काम छोड़ देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि पेंशन मिलेगी।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण न देकर आप अपनी बात रखें।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): इस सरकार ने फौजियों की बात करते हुए चुनाव लड़ा था और अब वह सरकार नि:शक्त फौजियों पर टैक्स लागू कर रही है।

(1250/MK/SM)

यह बड़े दु:ख की बात है। उसके बाद यह सरकार कहती थी कि 'वन रैंक वन पैंशन' अभी देखा जा रहा है। 'वन रैंक फाइव पेंशन' …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये विषय आपने रख दिया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जिस पर नोटिस दिया है, उसी पर जवाब मांग सकते हैं।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सेन्ट्रल फोर्स को, जब उनका देहांत होता है, मौत होती है तो उनको शहीद की मर्यादा दी जाए। ये तीन-चार मुद्दे हैं, ये बड़े मुद्दे नहीं हैं। फौजों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने एक नोटिस दिया था।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप सेन्ट्रल फोर्स को शहीदों की मर्यादा दीजिए और 'वन रैंक वन पेंशन' के बदले 'वन रैंक फाइव पेंशन' मत कीजिए…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जिस पर नोटिस दिया है, उसी पर बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): ये दो-चार मुद्दे हैं। छोटी-सी बात करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। आप इसके बारे में निश्चित रूप से कहिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय रक्षा मंत्री, एक सवाल पर जवाब दें। इनको दस सवाल उठाने की इजाजत नहीं है।

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने प्रश्न उठाया है कि पेंशन बढ़ने के कारण उनके ऊपर कुछ टैक्स इम्पोज किये गये हैं अपनी सेना के जवानों के ऊपर। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि डिफेंस प्रिपेरड्नस यानी रक्षा की तैयारियां और साथ ही साथ सेना के जवानों का इंट्रेस्ट यह हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है।

अध्यक्ष जी, मैं केवल किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता हूं। सारा देश इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है। 40 वर्षों तक हमारी सेना के जवान ओ.आर.ओ.पी. की मांग करते रहे, लेकिन बराबर उनको अंधेरे में रखा गया, बराबर उनको गुमराह किया गया। ...(व्यवधान) पहली बार यदि किसी सरकार ने इसे प्रभावी तरीके से लागू किया है तो हमारी सरकार ने लागू किया है। लेकिन जो प्रश्न यहां पर उठाया गया है, हमारे संज्ञान में यह बात आयी है। इसकी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद आपकी इजाजत से, अगर आप कहेंगे तो मैं सदन को भी अवगत करा दूंगा। ...(व्यवधान)

श्री विजय बघेल (दुर्ग): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले पांच दिनों से मैं आवेदन लगा रहा था, लेकिन आपने आज अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यह आपकी कृपा है। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन दुर्ग शाखा के गोडाउन में रखे पी.डी.एस. का चावल जो गरीबों को दिया जाता है उसके 20 बोरों में कांच के मिश्रण पाये गये थे। खाद्य विभाग ने दबिश देकर इसको जब्त किया था और गोडाउन मैनेजर द्वारा दो महाशय रखकर उसको साफ कराया जा रहा था जबकि अधिकारियों के मुताबिक वह चावल पूरा साफ नहीं हो सकता। उसे नष्ट किया जाना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, इस अनियमितता की जांच हो और जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई हो मैं यह निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री विजय बघेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती दिया कुमारी (राजसमन्द): आपने मुझे सदन में पहली बार बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं उनके लिए ताली बजाइए।

श्रीमती दिया कुमारी (राजसमन्द): बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द व राजस्थान प्रदेश के लोगों की एक बहुत समय से लंबित मांग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। यह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। इस लोक सभा क्षेत्र में मावली से मारवाड़ को जोड़ने के लिए जो रेलमार्ग है वह भारत का सबसे पुराना रेलमार्ग है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान देकर वर्ष 2017-18 के बजट में इस रेलमार्ग के गेज़ कन्वर्जन का काम स्वीकृत भी किया था तथा इसके लिए 1600 करोड़ रुपये का बजट भी सैंक्शन किया गया था, जिसको अगले वर्ष बढ़ाकर 2600 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(1255/YSH/AK)

महोदय, इस कार्य के लिए डी.पी.आर. का कार्य प्रगति पर आया, लेकिन यह रेलमार्ग टॉडगढ़ वन क्षेत्र से आया। यह रेलमार्ग टॉडगढ़ वन क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए डी.पी.आर. को बनाने के लिए वन विभाग की ओर से आपत्तियां उठाई जा रही हैं, इस कारण यह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इस समय तो यह कार्य बिल्कुल ही रुका हुआ है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी और पर्यावरण मंत्री जी से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे कि राजसमंद ही नहीं, बल्कि भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सहित आधे राजस्थान राज्य के यात्रियों और लाखों की संख्या में श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे की सुविधाओं का लाभ मिल सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती दिया कुमारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Hon. Speaker, Sir, I thank you very much for this opportunity.

My Nagapattinam Parliamentary constituency is a very backward and undeveloped constituency in Tamil Nadu. The main source of income for the people is fishing and agriculture, and they are totally dependent upon agriculture for their livelihood where around 15 lakh tonnes of paddy are being produced every year.

The Government of India had earlier permitted the Vedanta Group and ONGC to dig deep wells for the hydrocarbon project, which created a lot of resentment among the people and farmers. Recently, the Government of India, again permitted digging of another 104 deep wells for the same project. This has further created a lot of resentment among the farmers because it has totally spoilt not only the fertile land, but also the drinking water.

Hence, I would like to urge upon the Union Government, through this august House, to take necessary action to stop the ongoing project in the interest of the people. Thank you, Sir.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, I would like to associate with the issue raised by Shri M. Selvaraj.

माननीय अध्यक्ष : श्री सु. थिरुनवुक्करासर को श्री एम. सेल्वराज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एसोसिएट करने के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखकर टेबल ऑफिसर को दे दिया करें।

श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल (खडूर साहिब): अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहां का सदस्य हूँ और आपने आज मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया है।

मैं जिस कांस्टिट्यूएंसी (खडूरसाहिब) से आता हूँ, उसका पाकिस्तान के साथ लगा हुआ सबसे लम्बा बोर्डर है। वर्ष1965 और वर्ष 1971 की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान इसी क्षेत्र में हुआ था। पंजाब में जो 22 साल टेरेरिज्म रहा, उसमें इस क्षेत्र के करीब 11 हजार लोगों ने अपनी जान गवाईं, जिनमें मेरे पिताजी, जो उस टाइम मौजूदा एम.एल.ए. थे, उन्होंने भी शहादत दी थी। मुझ पर चार बार टैरेरिस्ट अटैक हुआ। मेरे शरीर पर आज भी गोलियों के निशान है।

मैं आपसे विनती करता हूँ, कि आप मुझे कृपया दो मिनट दे दीजिए, आप बेल न बजाए। हमारी मुश्किलें दूसरे क्षेत्रों से विपरीत हैं। आज पंजाब में जो पहले सिख मास्टर श्री गुरु नानक देव जी है, उनका हम नवम्बर में 550वां जन्मदिन मनाने जा रहे है। जो समिति है, मैं उसका सदस्य होने के नाते आपसे विनती करता हूँ कि 1 नवम्बर को यह कार्य होगा और सभी पार्टीज के सदस्यों का एक डेलिगेशन उसमें जरूर शामिल हो। एक करतारपुर कॉरिडोर बन रहा है, वह दो किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। हिन्दुस्तान सरकार ने काफी हिम्मत की है, पाकिस्तान के साथ मिलकर, मगर उसकी स्पीड कम है। उसे तेजी के साथ बनाना है, ताकि यह नवम्बर तक शुरू हो जाए। मैं विनती करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में ब्यास रिवर है, जब भी पानी का लेवल बढ़ जाता है। वहां कुछ फ्लड वगैरह आ जाती है, तो बहुत ज्यादा जमीन को काट के ले जाती है, जिससे करोड़ों रुपया हर साल उसके मुआवजे में देना पड़ता है। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इसके साइड्स पर धुसी बांध बनाया जाए जिससे जमीन का बचाव हो सके।